दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि : 19, मार्च, 2024

उदघोषित तिथि : 24, मई 2024

सि.वा.(वाणि.) 715/2022 व अंतर.आ.सं. 21396-21397/2022, 21428 21430/2022, 21794/2022, 21814/2022

ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड ..... वादी

के माध्यम से: वरिष्ठ अधिवक्तागण, श्री दुष्यंत दवे, श्री अखिल सिब्बल, के साथ अधिवक्तागण श्री यशवर्धन, श्री रिया मार्शल, सुश्री कृतिका नागपाल, श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला, श्री अक्षय गुप्ता, श्री अक्षत मालपानी, सुश्री आयुषी गौर, सुश्री असवरी जैन और श्री आदित्यराज पटोडिया।

बनाम

अन्नपूर्णा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, व अन्य .....प्रतिवादीगण

के माध्यम से: श्री नील मेसन, श्री विहान डांग, सुश्री प्रज्ञा जैन, श्री उज्जवल भार्गव और श्री आदित्य माथुर, प्र-5 के लिए अधिवक्तागण।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सेठी के साथ सुश्री समीक्षा गोदियाल, श्री गोविंद मनोहरन, श्री ए. कार्तिक,

सुश्री स्मृति सुरेश, सुश्री श्रीप्रिया, सुश्री गुंजन राठौर, श्री निश्चय शर्मा और श्री सुमेर सेठ, प्र-6 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. श्री संजीव नरूला :

अंतर. आ. 4065/2024 *(सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXXIX नियम 2 क के तहत)*

संक्षेप में विवाद

1. तत्काल मुकदमा 27 मई, 2021 को वादी, एक संगीत कंपनी जो संगीत और मनोरंजन सामग्री के उत्पादन, वितरण और मुद्रीकरण में विशेषज्ञता वाली एक संगीत कंपनी और प्रतिवादी सं. 6, गायन, नृत्य और अभिनय में जुड़े एक प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार के बीच एक उत्पादन समझौते के कथित उल्लंघन से उत्पन्न होता है। वादी का तर्क है कि उक्त समझौते के तहत, उक्त समझौते की अवधि के दौरान प्रतिवादी सं. 6 द्वारा बनाए गए गीतों/सामग्री में सभी कॉपीराइट वादी के पास निहित हैं। प्रतिवादी सं. 6 ने सामग्री बनाकर और तीसरे पक्ष (प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और 7 से 14) को प्रतिवादी सं. 5 के मंच

(यूट्यूब) पर इसे बढ़ावा देने और मुद्रीकृत करने की अनुमति देकर वादी के कॉपीराइट और विशिष्टता दायित्वों का उल्लंघन किया है। इस उल्लंघन ने वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिवादी सं. 6 ने आरोपों से इनकार किया है और वादी द्वारा मांगी गई राहत का विरोध करने के लिए कई कानूनी और तथ्यात्मक बचाव किए हैं।

2. मुकदमे के अंतिम निर्णय के लंबित होने पर, वादी ने निषेधाज्ञा के रूप में अंतरिम राहत मांगी। यह राहत शुरू में अंतरिम आधार पर दी गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इस न्यायालय की न्याय खंडपीठ ने 5 सितंबर, 2023 को आ.प्र.अ. (मू.प.)(वाणि.) 7/2023 में अपने फैसले में विशिष्ट शर्तों के साथ इसे बहाल कर दिया। फैसले में सीमित निषेधाज्ञा राहत दी गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी सं. 6 को भोजपुरी फिल्म उद्योग, मंचों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर गाने, अभिनय करने या नृत्य करने से नहीं रोका गया है।

3. उसके खिलाफ व्यादेश जारी होने के बावजूद, यह प्रतिवादी सं. 6 है जिसने आदेश XXXIX नियम 2क और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सि.प्र.सं.) की धारा 151 के तहत वादी के खिलाफ इस न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, और निषेधाज्ञा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया है। प्रतिवादी सं. 6 (आवेदक) का दावा है कि वादी (गैर-आवेदक सं. 1) ने प्रतिवादी सं. 6 के सहयोगियों को निषेधाज्ञा

आदेश की शर्तों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और गलत तरीके से बताया है, जिसमें यह गलत अर्थ लगाया गया है कि आदेश केवल वादी के साथ विशेष सहयोग की अनुमति देता है। प्रतिवादी सं. 6 के अनुसार, यह जानबूझकर गलत व्याख्या, न्यायलय की अवमानना के बराबर है। वादी ने अपने अवज्ञाकारी कृत्यों के माध्यम से प्रतिवादी सं. 6 के पेशेवर कामों में गंभीर रूप से बाधा डाली है और उसे काम करने का कोई अवसर नहीं दिया है, जबकि न्यायालय ने उसे विभिन्न प्लेटफार्मों और उद्योगों में काम करने की स्पष्ट अनुमति दी है। वादी ने आरोपों से इनकार करते हुए, वर्तमान कार्यवाही की स्थिरता का कड़ा विरोध किया है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

4. पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों पर विचार करने से पहले, इस आवेदन को दायर करने के पीछे की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना उचित होगा:

4.1 वादी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड, संगीत और मनोरंजन सामग्री के उत्पादन, एकत्रीकरण, वितरण और मुद्रीकरण के व्यवसाय में लगा हुआ है। प्रतिवादी सं. 6, श्री शत्रुघ्न कुमार जिन्हें खेसारी लाल यादव के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार हैं, जो गायन, नृत्य और अभिनय में शामिल हैं।

4.2 व्यापक बातचीत करने के बाद, वादी और प्रतिवादी सं. 6 ने 27 मई, 2021 को एक उत्पादन समझौता किया, जो 1 जून, 2021 से प्रभावी है। इसके अनुसार, वादी को मूल समझौते की अवधि के दौरान प्रतिवादी सं. 6 द्वारा बनाए गए सामग्री/गीतों में सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व प्रदान किया गया था। विशेष रूप से, प्रतिवादी सं. 6 ने सामग्री निर्माण/उत्पादन के लिए वादी के साथ विशेष सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और मूल समझौते में निर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर, इसके लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ संलग्न नहीं होने पर सहमति व्यक्त की।

4.3 इसके बाद, उभरे विवादों के अनुसार, पक्षों ने 7 फरवरी, 2022 की तारीख वाले एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसे 3 मार्च, 2022 को निष्पादित किया गया। तदनुसार, मूल समझौते की अवधि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा, मूल समझौते में कुछ संशोधन किए गए। मासिक गीत-वितरण कोटा को प्रति माह आठ (8) गीतों में समायोजित किया गया, जिसमें प्रति गीत के आधार पर भुगतान संरचित किया गया, जिसमें 10% वार्षिक लाभ हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा, विशिष्टता दायित्वों में ढील दी गई, जिससे प्रतिवादी सं. 6 को वादी के पहले इनकार के अधिकार के अधीन अन्य पक्षों के साथ जुड़ने की अनुमति मिली। प्रासंगिक रूप से, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व मूल समझौते से अपरिवर्तित रहा।

4.4 वादी ने वर्तमान मुकदमा यह आरोप लगाते हुए शुरू किया कि प्रतिवादी सं. 6 ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सामग्री बनाई थी और तीसरे पक्ष को प्रतिवादी सं.5 के मंच यूट्यूब पर ऐसी सामग्री प्रकाशित/अपलोड करके उसे बढ़ावा देने और मुद्रीकरण करने की अनुमति दी थी।

4.5 14 अक्टूबर, 2022 को वादी के पक्ष में *प्रथम दृष्टया* मामला पाते हुए, *एकपक्षीय अंतरिम* निषेधाज्ञा दी गई। अवरोध इस प्रकार व्यक्त किये गए:

> "26. *तदनुसार, प्रतिवादी सं.* 1 *से* 4 *और प्रतिवादी सं. 7 से* 14 *को प्रतिवादी सं.* 6 *द्वारा बनाई गई सभी सामग्रियों को दिखाने, जारी करने, लॉन्च करने, प्रसारित करने या मुद्रीकरण करने से रोक दिया गया है, जो कि यूट्यूब और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों जैसे स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक इत्यादि पर वादी के साथ किए गए उपरोक्त समझौते के तहत वादी के कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है, और प्रतिवादी सं.* 6 *भी अगली सुनवाई की तिथि तक वादी के साथ किए गए मूल समझौते और परिशिष्ट का उल्लंघन करते हुए किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा।*'

4.6 इसके बाद, सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत आवेदन [अंतर.आ. 19779/2022] पर, एकपक्षीय आदेश के माध्यम से दी गई निषेधाज्ञा को 6 जनवरी, 2023 के फैसले द्वारा निष्प्रभाव कर दिया गया। नतीजतन, अंतरिम निषेधाज्ञा [अंतर.आ.16789/2022] की मांग करने वाली वादी की अर्जी खारिज कर दी गई।

4.7 इस निष्प्रभावी आदेश को वादी ने खंडपीठ के समक्ष अपील में चुनौती दी थी। आ.प्र.आ. (मू.प.) (वाणि.) 7/2023 में 5 सितंबर, 2023 को दिए गए

विस्तृत फैसले में, खंडपीठ ने निष्प्रभावी आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया। हालांकि, इस बार निषेधाज्ञा विशिष्ट शर्तों पर जारी की गई थी, जो एकपक्षीय आदेश से अलग थी। यह इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

> *"88. तदनुसार, उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को ख़ारिज किया जाता है और यह न्यायालय प्रतिवादी सं. 1/प्रतिवादी सं. 6 को 30 सितंबर, 2025 तक किसी भी नए गाने के मुद्रीकरण के लिए प्रतिवादी सं. 2 से 5 और/या अपीलकर्ता/वादी के प्रतियोगी सहित किसी भी तीसरे व्यक्ति से जुड़ने से रोकता है, सिवाय इसके कि जब अपीलकर्ता/वादी उक्त गाने को लेने से इनकार कर दे, बशर्ते कि अपीलकर्ता/वादी इस न्यायालय की रजिस्ट्री में शेष शुल्क (यानी 2.20 करोड़ रुपये) जमा करके अपनी ईमानदारी साबित करे। उक्त राशि का भुगतान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश का पालन* के अनुसार होगा। *मामले को विवाद से परे रखने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 भोजपुरी फिल्म उद्योग के साथ-साथ राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मंचों पर अभिनय, गायन, नृत्य करना जारी रख सकते हैं, लेकिन वे अपने नए गाने वितरकों/संगीत कंपनियों/निर्माताओं/तीसरे पक्ष जैसे प्रतिवादी सं.2 से 5 आदि को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि अपीलकर्ता/वादी उक्त नए गीतों को लेने से इनकार नहीं कर देते।"*

4.8 वादी ने प्रतिवादी सं. 6 के सहयोगियों, वादी के प्रतिस्पर्धियों और यूट्यूब एलएलसी (प्रतिवादी सं. 5/गैर-आवेदक सं. 2) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न संस्थाओं को 21 सितंबर, 2023 की तिथि वाले कई नोटिस/संचार जारी करके उपरोक्त निर्देशों को लागू करने की मांग की। स्पष्टता के लिए ऐसे ही संचार का एक उदाहरणात्मक अंश नीचे दिया गया है:

"5. 14 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधात्मक आदेश 1 जारी किया, जिसमें प्रतिवादीगण को श्री खेसारी लाल यादव द्वारा बनाई गई किसी भी ऐसी सामग्री को दिखाने, जारी करने, लॉन्च करने, प्रसारित करने या उससे कमाई करने से रोकने का निर्देश दिया गया, जो जीएमजे के कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती हो, खासकर यूट्यूब, स्पोटिफ़ाई, जिओ सावन, विंक और अन्य जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर। श्री खेसारी लाल यादव को जीएमजे के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों का निर्माण करने से भी रोक दिया गया था। कृपया प्रतिबंधात्मक आदेश 1 के पैराग्राफ 25 और 26 को अनुलग्नक 1 के रूप में देखें।

6. 6 जनवरी, 2023 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आदेश ("6 जनवरी का आदेश") को निष्प्रभावी कर दिया। 6 जनवरी के आदेश से व्यथित होकर, जीएमजे ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील सं. (आ.प्र.आ. (मू.प.) (वाणि.) 7/2023) दायर की।

7. प्रतिबंधात्मक आदेश 2 के माध्यम से, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 6 जनवरी के आदेश को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया और परिणामस्वरूप प्रतिबंधात्मक आदेश 1 पूरी ताकत और प्रभाव के साथ लागू हुआ। इसके अलावा, प्रतिबंधात्मक आदेश 2 ने कलाकार को 30 सितंबर, 2025 तक किसी भी नए गाने के मुद्रीकरण के लिए किसी तीसरे व्यक्ति और/या जीएमजे के प्रतियोगी के साथ जुड़ने से स्पष्ट रूप से मना किया है और प्रतिबंधित किया है। कृपया अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न निरोधक आदेश 12 के पैराग्राफ 88 का संदर्भ लें।

... XXX... ... XXX... ... XXX...

12. उपरोक्त के आलोक में, हम आपसे आह्वान करते हैं कि:

क. इस नोटिस की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर और प्रतिबंधात्मक आदेश 1 के अनुपालन में, प्रतिबंधित गानों और श्री खेसारी लाल यादव द्वारा अवधि के दौरान बनाए गए किसी भी कंटेंट का मुद्रीकरण करना बंद कर दें और सुनिश्चित करें कि भविष्य की सभी आय, यदि कोई हो, हमारे मुवक्किल के लिए आपके द्वारा ट्रस्ट में रखी जाए;

ख. इस नोटिस की प्राप्ति के तुरंत बाद और 15 दिनों के भीतर, निषिद्ध गीतों के संबंध में आपके द्वारा उत्पन्न सभी आय और राजस्व के संबंध में लेखा प्रस्तुत करें, जिसका कॉपीराइट विशेष रूप से जीएमजे के पास है;

ग. इस नोटिस की प्राप्ति के तुरंत बाद और 30 दिनों के भीतर, प्रतिबंधित गानों के संबंध में आपके द्वारा अर्जित सभी आय और राजस्व का भुगतान जीएमजे को करें। यदि आप ऊपर दिए गए पैराग्राफ 12 में दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो हम पूरी तरह से आपकी लागत पर कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।"

4.9 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वादी के कानूनी नोटिस में न्यायालय द्वारा पारित सभी तीन प्रासंगिक आदेशों का संदर्भ दिया गया है - अर्थात एकपक्षीय आदेश, निष्प्रभाव आदेश और खंड पीठ आदेश - फिर भी, वादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खंडपीठ का आदेश (जिसे ऊपर "प्रतिबंधात्मक आदेश II" के रूप में संदर्भित किया गया है) का प्रभाव एकपक्षीय आदेश (जिसे ऊपर "प्रतिबंधात्मक आदेश I" के रूप में संदर्भित किया गया है) को बहाल करने का था। इस प्रकार, वादी ने प्रभावी रूप से नोटिस प्राप्तकर्ताओं से खंड पीठ के आदेश के विपरीत एकपक्षीय आदेश में जारी निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया।

4.10 उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए, प्रतिवादी सं. 6 ने यह आरोप लगाते हुए तत्काल आवेदन दायर किया है कि वादी के कानूनी नोटिस के अनुसार, प्रतिवादी सं. 6 के कई गाने, जो खंड पीठ के आदेश द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर थे, यूट्यूब सहित विभिन्न संगीत स्ट्रीमिंग

प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिए गए थे। इन संचारों में कानूनी कार्रवाई की वादी की धमकी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी सं. 6, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और नर्तक है, को किसी भी पेशेवर अवसर से वंचित कर दिया है। नतीजतन, प्रतिवादी सं. 6 का तर्क है कि वादी ने न्यायालय के निर्देशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और इसलिए, उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाना चाहिए।

4.11 21 फरवरी, 2024 को प्रतिवादी सं. 6 और वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनवाई के बाद, इस न्यायालय ने वादी के कार्यों को *प्रथम दृष्टया* न्यायालय की अवमानना माना और तदनुसार वादी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, वादी को व्यादेश के प्रवर्तन की मांग करने के लिए किसी भी पक्ष को सीधे पत्र लिखने से भी रोक दिया गया। उक्त आदेश में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"8. वादी 14 अक्टूबर, 2022 के एकपक्षीय आदेश को लागू नहीं कर सकता था, क्योंकि उक्त आदेश समाप्त हो चुका था। सबसे पहले, एकपक्षीय आदेश उसी को खाली करने वाले बाद के आदेश के साथ विलीन हो गया; और दूसरी बात, जबकि खंड पीठ ने निष्प्रभाव आदेश को अलग रखा, उसने एकपक्षीय आदेश को बहाल नहीं किया। इस प्रकार, खंड पीठ के आदेश के पैराग्राफ सं. 88 में वर्णित प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ जारी निषेधाज्ञा के निर्देश वर्तमान में प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ संचालित एकमात्र प्रतिबंध/बाधा हैं, और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, अपने नोटिस में, वादी को प्रासकर्ताओं को 14 अक्टूबर, 2022 के एकपक्षीय आदेश के अनुपालन में कार्य करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का गलत प्रतिनिधित्व है। यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है और बाध्यकारी निर्देशों*

का पालन न करने के लिए वादी को अवमानना के लिए उत्तरदायी बनाती है।

...XXX... ... XXX.. ...XXX...

10. वादी इस आदेश की एक प्रति संलग्न करेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों/संस्थाओं/प्लेटफार्मों को नए नोटिस भेजेगा, जिन्हें मूल रूप से नोटिस भेजे गए थे, इस आदेश के अपलोड होने की तारीख से 48 घंटे की अवधि के भीतर, अर्थात 24 फरवरी, 2024 को या उससे पहले। इसके अनुसार, वादी सुनवाई की अगली तारीख से पहले पूर्वोक्त निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई का वर्णन करते हुए एक शपथपत्र दायर करेगा।

11. इसके अलावा, चूंकि वादी ने न्यायलय के आदेशों की गलत व्याख्या की है, इसलिए यह न्यायालय यह स्पष्ट करना उचित समझती है कि वादी निषेधाज्ञा के आदेश को लागू करने के लिए किसी भी पक्ष को सीधे पत्र नहीं लिखेगा। इस मुद्दे पर, श्री सिब्बल का तर्क है कि यदि वादी को प्रवर्तन की मांग करने के लिए संबंधित संस्थाओं को सीधे लिखने की अनुमति नहीं है, तो इस न्यायलय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो जाएगी। हालांकि, न्यायालय इस तर्क को अस्थिर मानती है, क्योंकि खंड पीठ के आदेश की स्पष्टता और सटीकता यह सुनिश्चित करती है कि वादी के अधिकारों और हितों को प्रत्यक्ष एकतरफा प्रवर्तन कार्रवाइयों की आवश्यकता के बिना पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि वादी अपने आदेशों को लागू करने और इसके किसी भी उल्लंघन के मामले में, किसी भी आवश्यक चरण में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है। फिर भी, यह निर्देश वादी द्वारा न्यायालय के आदेशों के पूर्वोक्त दुरुपयोग के आलोक में जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन न्यायिक निगरानी के दायरे में रहे, जिससे प्रक्रियागत शुचिता के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा हो सके।"

4.12. उपरोक्त निष्कर्ष मामले के *प्रथम दृष्टया* आकलन पर आधारित थे, और वादी को तत्काल आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, फिर भी, वादी ने 21 फरवरी, 2024 के आदेश के खिलाफ अपील करने का

विकल्प चुना। हालांकि, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि 21 फरवरी, 2024 का आदेश *अंतरिम* आदेश था, मामले को आगे के विचार के लिए इस न्यायालय को वापस भेज दिया। इन परिस्थितियों में, 19 मार्च, 2024 को, इस न्यायालय ने उपरोक्त अनुशीर्षक वाले आवेदन के गुण-दोष पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्तागण की दलीलें सुनीं।

<u>आवेदक/ प्रतिवादी सं. 6 की ओर से दलीलें</u>

5. श्री संदीप सेठी, प्रतिवादी सं. 6 के वरिष्ठ अधिवक्ता, ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

5.1 वादी ने प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ़ लागू होने वाले प्रतिबंधात्मक निर्देशों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके खंड पीठ के आदेश के तहत दिए गए निषेधाज्ञा की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। वादी द्वारा जारी किए गए कानूनी नोटिस में, उन्होंने दावा किया है कि खंड पीठ के आदेश का प्रभाव एकपक्षीय आदेश को बहाल करने का था, जो *"पूरी ताकत और प्रभाव के साथ"* लागू होगा। खंड पीठ द्वारा दिए गए विशिष्ट निषेधाज्ञा के बारे में जानकारी होने के बावजूद, वादी ने अपने कानूनी नोटिस के प्राप्तकर्ताओं से एकपक्षीय आदेश के अनुसार कार्रवाई करने का आह्वान किया है, जो अब लागू या अस्तित्व में नहीं था। इस तरह की कार्रवाइयां वादी के अवज्ञाकारी आचरण को दर्शाती हैं।

5.2 खंड पीठ के आदेश में जारी निर्देशों ने एकपक्षीय आदेश द्वारा जारी निषेधाज्ञा निर्देशों की कठोरता को शिथिल कर दिया। खंड पीठ के आदेश ने केवल *"उसके नए गीतों"* की बिक्री पर रोक लगाई जब तक कि वादी ने इसे लेने से इनकार नहीं कर दिया। इसका अर्थ खंड पीठ के आदेश के बाद निर्मित गीतों से लगाया जाना चाहिए, यानी 5 सितंबर, 2023 के बाद। इसके अलावा, *"अपने नए गीतों"* वाक्यांश का विशिष्ट उपयोग यह दर्शाता है कि निषेधाज्ञा निर्देशों में केवल प्रतिवादी सं. 6 द्वारा *निर्मित* गीत शामिल हैं, यानी, उनके द्वारा उत्पन्न और उनके स्वामित्व वाले गीत, अन्य गीत नहीं जिनमें उन्होंने केवल एक अभिनेता, गायक या नर्तक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। हालाँकि, वादी के कानूनी नोटिस के कारण, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा निर्मित नहीं किए गए विभिन्न गीतों को हटा दिया गया है। इस प्रकार, एकपक्षीय आदेश के प्रवर्तन की मांग करने वाले वादी के कानूनी नोटिस ने न केवल प्रतिवादी सं. 6 को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि खंड पीठ के आदेश द्वारा जारी निर्देशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और उनका उल्लंघन किया है।

5.3 सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 2क के तहत वर्तमान आवेदन बनाए रखने योग्य है। उक्त प्रावधान को पढ़ने पर पता चलता है कि इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन या जिन शर्तों पर ऐसा निषेधाज्ञा दी गई थी, के कारण आहत होकर लागू किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खंड पीठ के आदेश ने प्रतिवादी सं. 6 को *"भोजपुरी फिल्म उद्योग के*

साथ-साथ राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मंचों पर "अभिनय, गायन, नृत्य" जारी रखने की स्वतंत्रता दी..."। दी गई इस स्वतंत्रता के मद्देनजर, जो खंड पीठ द्वारा दी गई सीमित निषेधाज्ञा की एक आवश्यक शर्त है, प्रतिवादी सं. 6 को खंड पीठ के आदेश द्वारा दी गई निषेधाज्ञा का लाभार्थी माना जाएगा। इसलिए, इस तथ्य को देखते हुए कि वादी के अवज्ञाकारी आचरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता में कटौती हुई है, प्रतिवादी सं.6 सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX के नियम 2क के तहत राहत मांगने का हकदार होगा।

5.4. भले ही आवेदन सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX के नियम 2क के तहत अनुरक्षणीय न हो, तब भी न्यायालय वादी द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग का संज्ञान लेने और उस संबंध में सुधारात्मक निर्देश जारी करने में शक्तिहीन नहीं होगा। सि.प्र.सं. की धारा 151 को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के साथ पढ़ने पर, न्यायालय को पक्षों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। वास्तव में, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सि.प्र.सं. की धारा 151 न्यायालय को प्रक्रिया के दुरुपयोग के समाधान के लिए आवश्यक पाए जाने पर वाद को खारिज करने तक का अधिकार देती है। इस तर्क के समर्थन में ***विदुर इम्पेक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार खन्ना व अन्य*** में इस न्यायालय के फैसले और ***के.के. वेलुसामी बनाम एन पलानीसामी*** में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया जाता है।

5.5 वादी ने न्यायालय के निर्देशों का वास्तव में गलत व्याख्या का दावा करके अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास किया है। अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए यह स्पष्टीकरण टिकाऊ नहीं है। वादी की अवज्ञाकारी कार्रवाई न्यायालय के आदेशों में किसी अस्पष्टता से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह खंड पीठ के आदेश की शर्तों को अस्पष्ट करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाता है। वादी की सद्भावना की कमी खंड पीठ के आदेश के स्पष्ट प्रावधानों के लिए उनकी जानबूझकर उपेक्षा और अवमानना के लिए *प्रथम दृष्टया* उत्तरदायी पाए जाने के बावजूद किसी भी बिना शर्त माफ़ी के अभाव से स्पष्ट होती है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय वादी को निषेधाज्ञा के अपने उल्लंघन का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दे सकता है, इसे केवल कथित रूप से वास्तव में गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार ठहराकर, और इस तरह के आचरण को अवमानना के बराबर माना जाना चाहिए। यह तर्क ***ऑल बंगाल एक्साइज लाइसेंसीज एसोसिएशन बनाम राघबेन्द्र सिंह व अन्य*** में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और **एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम वर्षा जोशी व अन्य** में इस न्यायालय की टिप्पणियों से पुष्ट होता है।

5.6. वर्तमान मामला वादी द्वारा केवल नकारात्मक वाचा को लागू करने के लिए दायर किया गया है, न कि पक्षों के बीच समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए। इस प्रकार, वादी समझौते के अनुसार आठ (8) गीतों की डिलीवरी के

लिए दबाव नहीं डाल सकता है, यह स्थिति खंड पीठ के आदेश में पैराग्राफ सं. 49 में टिप्पणियों द्वारा समर्थित है।

5.7. वादी द्वारा खंड पीठ के आदेश के स्पष्ट उल्लंघन को देखते हुए, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए, और वादी को तीसरे पक्ष को सीधे नोटिस जारी करने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा, वादी के नोटिस के अनुसार हटाए गए गानों को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

<u>गैर-आवेदक सं. 1/वादी की ओर से दलीलें</u>

6. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का कड़ा खंडन किया है। वादी की ओर से उनके द्वारा दी गई दलीलों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

6.1 वर्तमान आवेदन सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX के नियम 2क के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। ऐसा आवेदन केवल उस पक्ष द्वारा दायर किया जा सकता है जिसके पक्ष में सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत निषेधाज्ञा आदेश दिया गया है, और केवल उस पक्ष के खिलाफ जिसके खिलाफ ऐसा निषेधाज्ञा लागू होता है। वर्तमान मामले में, खंड पीठ के आदेश प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में कोई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, वादी को जारी किया गया एकमात्र निर्देश न्यायालय में एक मुद्रा जमा करने से संबंधित था, जिसे प्रतिबंध

के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी सं. 6 के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि वादी ने खंड पीठ के आदेश में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है, और इस प्रकार, तत्काल आवेदन दायर करने का कोई कारण नहीं है, जिसे शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में, ***भारतीय खाद्य निगम बनाम सुखदेव प्रसाद***, और ***बिहार राज्य बनाम रानी सोनाबती कुमारी*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, साथ ही इस न्यायालय के ***सीतल दास राक्यान व अन्य बनाम जैन खरतरगच्छ संघ (पंजीकृत) व अन्य*** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

6.2 यह आवेदन केवल न्याय खंडपीठ के आदेश द्वारा जारी निर्देशों को दरकिनार करने के लिए दायर किया गया है। यद्यपि प्रतिवादी सं. 6 ने खंड पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यह अभी भी दोषों के तहत लंबित है। इस प्रकार, उक्त उपाय का पूरी लगन से पालन किए बिना, प्रतिवादी सं.6 ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से खंड पीठ के आदेश के प्रभाव को गलत रूप से विफल करने की कोशिश की है। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि, 21 फरवरी, 2024 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी सं. 6 ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने गीतों की रिलीज़ को मंजूरी देने के लिए तीसरे पक्ष को उक्त आदेश के प्रभाव को

गलत तरीके से प्रस्तुत करके अपने उल्लंघनकारी कार्यों को तेज कर दिया है। इस तरह की कार्रवाइयां स्पष्ट रूप से वर्तमान आवेदन दायर करने में प्रतिवादी सं. 6 की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती हैं।

6.3 वर्तमान आवेदन की स्थिरता पर उठाई गई आपत्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी के कार्य खंड पीठ के आदेश की किसी भी अवज्ञा के बराबर नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 6 यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि वादी के नोटिस के अनुसार जो गाने हटाए गए हैं, वे पक्षों के बीच समझौते से संबंधित नहीं थे और खंड पीठ के आदेश द्वारा आच्छादित नहीं किए गए थे। एक बार जब निष्प्रभाव आदेश को ख़ारिज कर दिया गया, तो खंड पीठ की आदेशं के माध्यम से दी गई निषेधाज्ञा वाद और अपील में विशेष रूप से उल्लिखित सभी गानों के साथ-साथ समझौते का उल्लंघन करने वाले गानों पर भी लागू होगी। इस प्रकार, अन्य तृतीय-पक्ष प्लेटफार्मों सहित ऐसे गीत, खंड पीठ के आदेश के शर्तों के विपरीत जारी होंगे। ***सीता राम बनाम बलबीर*** में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क से इस दलील को बल मिलता है।

6.4. प्रतिवादी सं. 6 यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी के कानूनी नोटिस के प्राप्तकर्ताओं ने प्रतिवादी के वीडियो को केवल वादी द्वारा एकपक्षीय आदेश के आह्वान के आधार पर हटा दिया। वादी द्वारा जारी किए गए नोटिस संगीत उद्योग में स्थापित संस्थाओं को भेजे गए थे, जिनके पास आधिकारिक कानूनी सलाह तक पहुँच थी। इसके अलावा, वर्तमान मामले के प्रक्रियात्मक

इतिहास के पूर्ण खुलासे के साथ, खंड पीठ के आदेश को लागू करने के लिए सद्भावपूर्वक नोटिस भेजे गए थे। वास्तव में, एकपक्षीय आदेश, निष्प्रभाव आदेश और खंड पीठ के आदेश सभी ऐसे संचारों के साथ संलग्न थे। इसलिए, सामग्री के हटाने को इस तथ्य के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं माना जा सकता है कि ऐसे प्राप्तकर्ता, जिनमें से कई वादी के प्रत्यक्ष प्रतियोगी हैं, जिनके पास उनके निर्देशों पर बिना सोचे-समझे कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं है, ने सही ढंग से स्वीकार किया था कि उक्त गीत खंड पीठ के आदेश का उल्लंघन करते थे। जैसा कि यह हो सकता है, 21 फरवरी, 2024 को जारी निर्देशों के संदर्भ में, वादी द्वारा ऐसी संस्थाओं को स्पष्टीकरण संचार भेजा गया है, और इस आशय का एक अनुपालन शपथपत्र दायर किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी सं.6 की शिकायत का समाधान हो गया है।

6.5 वादी द्वारा अपने कानूनी नोटिस में एकपक्षीय आदेश का आह्वान सद्भावना से एक गलती के कारण किया गया था। हालाँकि, उनकी ओर से यह गलती वादी को खंड पीठ के आदेश के प्रवर्तन की मांग करने के लिए आगे कानूनी नोटिस जारी करने से पूरी तरह से रोकने का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसा निर्देश वादी के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। वादी को न्यायालय के आदेशों को उजागर करने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार है कि कुछ गाने इसके उल्लंघन में हैं। जबकि ऐसे नोटिस के प्राप्तकर्ता असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, इस स्थिति में वादी

उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहारा लेने का विकल्प चुन सकता है, हालाँकि, वादी को पहली बार में न्यायालय से संपर्क करने के लिए मांग करना एक अतार्किक अवरोध होगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः तीसरे पक्ष को खंड पीठ आदेश का पहले अनुपालन करने का अवसर दिए बिना अवमानना कार्यवाही में घसीटा जाएगा।

6.6 वादी के खिलाफ दीवानी या आपराधिक अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय के किसी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की कोई अवज्ञा नहीं है, या न्यायालय को दिए गए किसी भी उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है। इस प्रकार, वादी को सिविल अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2(1)(ख) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, न तो न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2(1)(ग) के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना लगाने का कोई मामला बनता है, न ही इस तरह की कार्रवाई शुरू करने के लिए कड़े प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं पूरी की गई हैं। ये तर्क ***कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय***, ***एल.पी. मिश्रा (डॉ) बनाम यूपी राज्य***, ***पल्लव शेठ बनाम कस्टोडियन***, ***बाल ठाकरे बनाम हरीश पिंपलखुटे,*** और ***बिमन बसु बनाम कल्लोल गुहा ठाकुरता*** व अन्य में दी गई टिप्पणियों पर आधारित हैं।

6.7 यह भी तर्क दिया गया है कि जबकि प्रतिवादी सं. 6 ने इस तथ्य से पार पाने के लिए कि वर्तमान आवेदन स्वीकार्य नहीं है, न्यायालय द्वारा सि.प्र.सं. की धारा 151 को लागू करने पर जोर दिया है, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। उक्त प्रावधान केवल उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो और इसे वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने या ऐसे उपाय बनाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता जो सि.प्र.सं. के तहत परिकल्पित नहीं हैं। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी सं. 6 के पास पर्याप्त उपाय हैं जिनका लाभ उनकी शिकायत के निवारण के लिए उठाया जा सकता है और इस प्रकार वादी को अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 पर विशेष रूप से भरोसा करने का कोई अवसर नहीं है। कानून की यह स्थापित स्थिति ***माई पैलेस म्यूचुअल एडेड को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम बी. महेश व अन्य*** में विस्तृत है।

6.8. प्रतिवादी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे सभी उन तथ्यों और परिस्थितियों से अलग होने में सक्षम हैं जो वर्तमान मामले में न्यायालय के समक्ष हैं।

6.9. वादी की ओर से अवमानना का कोई मामला नहीं बनता। किसी भी मामले में, चूंकि वादी द्वारा स्पष्टीकरण संदेश पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए वादी द्वारा एकपक्षीय आदेश के गलत आह्वान से होने वाले नुकसान, यदि कोई

हो, की भरपाई हो चुकी है। इस प्रकार, वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

7. सि.प्र.सं. का आदेश XXXIX अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेशों से संबंधित है। आदेश XXXIX का नियम 2क विशेष रूप से निषेधाज्ञा की अवज्ञा या उल्लंघन के परिणामों को संबोधित करता है। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:

"आदेश XXXIX
अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतर्वर्ती आदेश
अस्थायी निषेधाज्ञा
...xxx... ... xxx... ... xxx.....

2क. अवज्ञा या निषेधाज्ञा के उल्लंघन का परिणाम

(1) नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी निषेधाज्ञा या पारित किसी अन्य आदेश की अवज्ञा की स्थिति में या उन शर्तों के भंग होने की स्थिति में, जिन पर निषेधाज्ञा दी गई थी या आदेश पारित किया गया था, निषेधाज्ञा देने वाला या आदेश देने वाला न्यायालय या कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अंतरित की गई है, ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध रखने का भी आदेश दे सकता है, जब तक कि इस बीच न्यायालय उसकी रिहाई का निर्देश न दे।

(2) इस नियम के अधीन की गई कोई भी कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगी, जिसके अंत में, यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है, तो कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकेगा और प्राप्त राशि में से न्यायालय पीड़ित पक्ष को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे और शेष राशि, यदि कोई हो, उसके हकदार पक्ष को देगा।"

8. इस प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायालय के पास निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले या ऐसे आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पक्ष के विरुद्ध दंडात्मक उपाय करने का अधिकार है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान पक्ष-विशिष्ट नहीं है, जिसका अर्थ है कि यदि न्यायालय ऐसा आदेश जारी करता है जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है जैसे *यथास्थिति बनाए रखना*, या तीसरे पक्ष पर, तो कोई भी पक्ष संभावित रूप से दूसरे के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि आदेश का उल्लंघन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा आदेश पारस्परिक रूप से लागू होता है, और दोनों पक्ष इसका अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, ऐसी स्थितियों में जहाँ आदेश दोनों पक्षों (वादी और प्रतिवादी) को प्रभावित करता है, किसी भी पक्ष द्वारा या विशेष रूप से निर्देशित किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई भी उल्लंघन अवमानना का आधार हो सकता है, यदि यह दिखाया जा सकता है कि उल्लंघन करने वाले पक्ष को आदेश के बारे में पता था और उसके पास इसका अनुपालन करने की क्षमता थी। नतीजतन, केवल यह तथ्य कि वर्तमान आवेदन प्रतिवादी सं. 6 द्वारा आदेश XXXIX नियम 2क का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, इसे ऐसा नहीं करेगा कि यह मान्य योग्य नहीं है।

9. जैसा भी हो, आदेश XXXIX नियम 2 क के पीछे मुख्य उद्देश्य न्यायालय को अवज्ञा के मामलों में संपत्ति की कुर्की या सिविल जेल में किसी व्यक्ति को

हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करना है, जो कि न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जब कोई पक्ष न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करता है, तो न्यायालय की प्रभावी रूप से कार्य करने और कानून के शासन को बनाए रखने की क्षमता को चुनौती दी जाती है। अवमानना शक्तियाँ गैर-अनुपालन के खिलाफ़ निवारक के रूप में कार्य करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि न्यायालय के निर्णयों और निर्देशों का सम्मान और कार्यान्वयन किया जाए। अवमानना शक्तियाँ न्यायपालिका के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। न्यायालयों को ऐसी संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जहाँ कानून लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं, और जिनके आदेशों का पालन किया जाता है। अवज्ञा को दंडित करके, न्यायालय अपने अधिकार और सम्मान की पुष्टि करता है। कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवमानना शक्तियाँ भी आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय किसी एक पक्ष को गुजारा भत्ता या बच्चे के भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश देता है और पक्ष इसका पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे आदेश के इच्छित लाभार्थी के वित्तीय अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए संपत्ति की कुर्की या कारावास आवश्यक हो सकता है। ये शक्तियां निर्देशों और निर्णयों के समय पर अनुपालन को प्रोत्साहित करके कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद करती हैं, जिससे लंबी मुकदमेबाजी से

बचा जा सकता है और प्रवर्तन पर अतिरिक्त न्यायालय संसाधनों को खर्च करने से बचाया जा सकता है।

10. हालांकि, आदेश XXXIX नियम 2 क के तहत सिविल अवमानना के मामलों में, अवमानना की कार्रवाई उस विशिष्ट पक्ष के खिलाफ निर्देशित की जानी चाहिए जो न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अधीन है। यह नियम विशेष रूप से न्यायालय द्वारा निर्धारित पक्षों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के अंतरिम आदेशों के गैर-अनुपालन को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। सि.प्र.सं. का आदेश XXXIX नियम 2क केवल निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन के मामले में या ऐसे आदेश दिए जाने की शर्तों पर लागू होता है। इस प्रकार, इसका उपयोग केवल उस पक्ष द्वारा किया जा सकता है जिसके पक्ष में सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत निषेधाज्ञा आदेश दिया गया है, और उस पक्ष के खिलाफ जिसे उक्त आदेश के संचालन द्वारा निषेधाज्ञा दी गई है। वर्तमान मामले में, सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत पारित खंड पीठ के आदेश ने प्रतिवादी सं. 6 को सितंबर 2025 तक नए गानों के मुद्रीकरण के लिए तीसरे पक्ष के साथ जुड़ने से रोक दिया। हालांकि, खंड पीठ द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसे वादी पर अवरोध के रूप में कार्य करने के लिए समझा जा सके। जैसा कि श्री दवे ने बताया, वादी पर लगाई गई एकमात्र शर्तें न्यायालय में धन जमा करने से संबंधित हैं, जिसका विधिवत पालन किया गया है। वादी के खिलाफ नियम 1 या 2 के तहत इस तरह के निषेधाज्ञा या आदेश के अभाव में, किसी

भी अवज्ञा की संभावना नहीं है - चाहे वह जानबूझकर हो या अन्यथा। इसलिए, प्रतिवादी सं. 6 के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि वादी ने खंड पीठ के आदेश में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। फिर भी हमें यह देखना चाहिए कि न्यायालय ने *प्रथम दृष्टया* निर्धारण के आधार पर शुरू में वादी के आचरण को अवज्ञाकारी पाया, हालांकि, तथ्यों और लागू कानून की विस्तृत जांच करने पर, न्यायालय को वादी के इस तर्क में योग्यता मिलती है कि तत्काल आवेदन सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 2क के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है।

11. उस ने कहा, न्यायालय श्री सेठी से इस हद तक सहमत है कि वादी के अपने कानूनी नोटिस में पूर्व-पक्षीय आदेश के आह्वान को वास्तविक गलती के रूप में नहीं कहा जा सकता है जैसा कि वादी द्वारा प्रचारित किया जाना है। उनके आचरण को उचित ठहराने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण आश्वस्त करने वाला नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि नोटिस में केवल अनजाने में एकपक्षीय आदेश का आह्वान नहीं किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि *"प्रतिबंधात्मक आदेश 1 पूरी ताकत और प्रभाव के साथ लागू होता है"*। न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए कि वादी कंपनी, विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार के मार्गदर्शन और संगीत उद्योग के भीतर अपने संचालन के साथ, कानूनी पेचीदगियों और कॉपीराइट मुद्दों से पूरी तरह परिचित है। ऐसी परिस्थितियों में, उनके द्वारा जारी किए गए कानूनी नोटिस में जानबूझकर

गलत संचार होता है, जो संभवतः उनके हितों को अधिक आक्रामक तरीके से लागू करने के इरादे से होता है, जो वास्तव में वादी की ईमानदारी को धुंधला करता है। न्यायालय के निर्देशों की गलत व्याख्या करने के लिए वादी के तर्क में तत्वों का अभाव है और यह समझाने में विफल रहता है। परिस्थितियों को देखते हुए, वादी की हरकतें उचित कानूनी आचरण से विचलन का संकेत देती हैं। फिर भी, यह अनुचितता आदेश XXXIX नियम 2क के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक कठोर मानदंडों को पूरा नहीं करती है। न्यायालय की अवमानना, विशेष रूप से सिविल अवमानना के मामलों में, न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना पर निर्भर करती है। खंड पीठ के आदेश वादी पर कोई निषेधाज्ञा या विशिष्ट निर्देश नहीं लगाता है जिसे जानबूझकर अवज्ञा के रूप में समझा जा सके। इस प्रकार, सिविल अवमानना स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, और आदेश XXXIX नियम 2क, एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्राधिकार होने के कारण, इस गलती को ठीक करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

12. अब हम न्यायालय अवमान अधिनियम के प्रावधानों की ओर मुड़ते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि वर्तमान मामला उक्त परिनियम के तहत किसी कार्रवाई को आकर्षित करता है या नहीं। न्यायालय अवमान अधिनियम "सिविल अवमानना" को "*किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रियाओं की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए*

गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन" के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान मामले में, वादी के विरुद्ध न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। इसके अलावा, वादी द्वारा न्यायालय को दी गई कोई भी वचनबद्धता नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया हो। ***भारतीय खाद्य निगम*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी पक्ष के विरुद्ध न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश का अस्तित्व सिविल अवमानना के लिए एक आवश्यक शर्त है। न्यायालय से ऐसे किसी स्पष्ट निर्देश की अनुपस्थिति में जिसकी जानबूझकर अवज्ञा की गई हो, वर्तमान मामले में नागरिक अवमानना को लागू करने के लिए आवश्यक मानदंड पर्याप्त नहीं हैं।

13. दूसरी ओर, न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत "आपराधिक अवमानना" में कोई भी प्रकाशन या कार्य शामिल है जो न्यायालय के अधिकार को आघात पहुंचाता है या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, न्यायिक कार्यवाही को हानि पहुंचाता या हस्तक्षेप करता है, या न्याय प्रशासन को बाधित करता है। न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या भारत के महाधिवक्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति से या उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव पर आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। वर्तमान मामले में ये शर्तें स्पष्ट रूप से पूरी नहीं हुई हैं। आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया मनमाने ढंग से की जाने वाली कार्यवाही से सुरक्षा के लिए

कठोर है जो न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर सकती है। महाधिवक्ता से सहमति या न्यायालय द्वारा स्वयं पहल की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक अवमानना गंभीर उल्लंघनों से संबद्ध हो जो वास्तव में न्यायिक प्रशासन को बाधित करती है। ***बाल ठाकरे (पूर्वोक्त)*** में निर्धारित सिद्धांत संकेत देते हैं कि आपराधिक अवमानना की कार्रवाई उन कार्यों के लिए आरक्षित होनी चाहिए जो न्यायिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से खतरे में डालते हैं, जो इस मामले में स्पष्ट नहीं है। यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वादी के कार्यों ने न्यायालय को निंदित किया, किसी न्यायिक कार्यवाही को आघात पहुँचाया, या किसी भी तरह से न्याय प्रशासन को बाधित किया। गलत संचार ने न्यायालय के अधिकार को कम नहीं किया या इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया। इन विचारों को देखते हुए, वादी का आचरण, संभवतः विभिन्न कानूनी सिद्धांतों के तहत कार्रवाई योग्य नैतिक मानकों का उल्लंघन करते हुए, संभवतः अपकृत्य कार्रवाई को आमंत्रित करता है, लेकिन न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत परिभाषित न्यायालय की सिविल या आपराधिक अवमानना नहीं करता है।

14. यह ध्यान देने योग्य है कि वादी की हरकतें, हालांकि शुरू में गलत थीं, लेकिन उन्हें सद्भावनापूर्वक सुधारा गया। वादी ने गलती को सुधारने के प्रयास को प्रदर्शित करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने और उस आशय का अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने सहित त्वरित सुधारात्मक उपाय किए। यह

सक्रिय दृष्टिकोण उनके शुरुआती गलत कदम की गंभीरता को कम करता है, इस प्रकार न्यायालय की अपेक्षाओं और प्रक्रियात्मक अखंडता के साथ संरेखित होता है। ये कार्य ***भारतीय खाद्य निगम*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप भी हैं, जहां न्यायालय ने प्रक्रियात्मक खामियों के प्रभावों को कम करने में सुधारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया था। इस प्रकार, न्यायालय ने वर्तमान अवमानना कार्यवाही की उपयुक्तता निर्धारित करने में इन सुधारात्मक कार्रवाइयों को ध्यान में रखा है। इसके अलावा, अवमानना मामलों में दंडात्मक उपायों को स्पष्ट और जानबूझकर अवज्ञा के उदाहरणों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जो इस मामले में स्पष्ट नहीं हैं।

15. प्रतिवादी सं. 6 द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले में उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों से अलग हैं। ***केके वेलुस्वामी (पूर्वोक्त) और विदुर इम्पेक्स (पूर्वोक्त)*** में, सि.प्र.सं. की धारा 151 का आह्वान उन मामलों की अनूठी विशिष्टताओं पर आधारित था। इन निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सि.प्र.सं के भीतर कोई लागू विशिष्ट प्रावधान है तो धारा 151 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट प्रक्रियात्मक नियम उपलब्ध होने और लागू होने पर निहित शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। इसके अलावा, न तो ***एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट (पूर्वोक्त)*** और न ही ***ऑल बंगाल एक्साइज लाइसेंसीज एसोसिएशन (पूर्वोक्त)*** में उस पक्ष के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा लागू थी जिसने अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। दोनों

मामलों में, न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या की दलील को खारिज कर दिया गया क्योंकि निषेधाज्ञा का उल्लंघन उस पक्ष द्वारा किया गया था जिसके खिलाफ ऐसा निषेधाज्ञा दिया गया था। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि, वर्तमान मामले में, वादी के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं है।

16. वादी के शुरुआती संचार को ध्यान में रखते हुए, जो न केवल अनुचित थे बल्कि जानबूझकर भ्रामक प्रतीत होते थे, यह विचार करना उचित है कि क्या न्यायालय को इस मामले में देखे गए कदाचार को संबोधित करने और सुधारने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इस मोड़ पर, सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के विस्तार और दायरे को पहचानना आवश्यक है। यह प्रावधान न्यायालय को न्याय की मांगों को बनाए रखने के लिए *न्यायिक कार्य* करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रावधान का प्रयोग अक्सर न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदेश देने या इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। यह न्यायिक शक्ति के भंडार के रूप में कार्य करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियात्मक तकनीकियों द्वारा कानून की प्रक्रिया को बाधित न किया जाए, यानी, अंतर्निहित शक्तियों को उन स्थितियों को शुरू करने के लिए लागू किया जा सकता है जहां प्रक्रियात्मक कानून मूल न्याय देने में अक्षम हो जाता है। इस प्रकार, आदेश XXXIX नियम 2क की प्रक्रियात्मक सीमाओं से न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ कम नहीं

होंगी। इस समझ को ***के.के. वेलुस्वामी (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों में समर्थन मिलता है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ व्यापक हैं और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। इसके अलावा, जैसा कि ***माई पैलेस म्यूचुअली एडेड को. सोसाइटी (पूर्वोक्त)*** में उल्लेख किया गया है, सि.प्र.सं. की धारा 151 यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि न्याय दिया जाए, और तकनीकीओं द्वारा बाधा डाले बिना कानून की प्रक्रिया को बरकरार रखा जाए।

17. साथ ही, न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत इस बात को रेखांकित करते हैं कि धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत अंतर्निहित शक्तियों का संयम से और केवल तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब कोई विशिष्ट प्रावधान लागू न हो। इसके अलावा, जैसा कि ***बाल ठाकरे (पूर्वोक्त)*** में जोर दिया गया है, अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए और अत्यधिक नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रियात्मक सीमाओं को लांघे बिना न्याय किया जाए। न्यायालय को किसी भी गलत काम को सही करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पक्षों को सद्भावनापूर्वक अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना चाहिए। इसलिए, जबकि न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है, फिर भी वह उसी का

उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि वादी ने अपनी गलती को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। हालांकि, न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि आगे बढ़ते हुए, यदि वादी तीसरे पक्ष के साथ संचार के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को लागू करने में संलग्न होता है, तो उन्हें किसी भी संभावित गलत प्रदर्शन से बचने के लिए न्यायालय के निर्देशों का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। यह शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है कि वादी की भावी कार्रवाई पारदर्शी हो तथा न्यायिक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहे।

<u>निष्कर्ष</u>

18. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, आदेश XXXIX नियम 2क सि.प्र.सं. के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 6 के खिलाफ जारी की गई थी, न कि वादी के खिलाफ। नतीजतन, 21 फरवरी, 2024 के आदेश के माध्यम से वादी पर लगाए गए प्रतिबंध, विशेष रूप से न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश को लागू करने के लिए किसी भी पक्ष के साथ सीधे संचार को प्रतिबंधित करते हुए, वापस लिए जाते हैं। वादी की हरकतें, हालांकि संदिग्ध थीं और यकीनन उनमें जानबूझकर गलत संचार के तत्व शामिल थे, बाद में उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी करके सद्भावनापूर्वक सही किया गया, जो गलती को सुधारने के लिए एक वास्तविक प्रयास को दर्शाता है। ये सुधारात्मक उपाय अवमानना कार्यवाही को बंद करने का औचित्य साबित करते हैं और वादी के

खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के आह्वान की मांग नहीं करते हैं, सिवाय निम्नलिखित कुछ निर्देशों के:

18.1. वादी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन के लिए तीसरे पक्ष के साथ भविष्य में कोई भी संचार स्पष्ट और सटीक हो, जिससे किसी भी अस्पष्टता या गलत प्रदर्शन की संभावना समाप्त हो जाए।

18.2. वादी द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रवर्तन नोटिस में प्रासंगिक न्यायालय के आदेशों का एक व्यापक सारांश शामिल होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से निषेधाज्ञा या निर्देशों के दायरे और सीमा को चित्रित करता हो।

19. पूर्वगामी निर्देशों के साथ, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

न्या. श्री संजीव नरूला

24 मई 2024/*डीजी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*